



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257025  
CG-DL-E-10092024-257025

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946

No. 511]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 553(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिसे केंद्र सरकार उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप धारा (2) के तहत तैयार करने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित आम लोगों और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने पर अथवा उसके बाद उक्त मसौदा नियम पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

मसौदा नियमों में निहित प्रस्तावों पर यदि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज करना चाहे या सुझाव देना चाहे तो वह उसे निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन नई दिल्ली-110001 को डाक द्वारा या [soil-dipp@nic.in](mailto:soil-dipp@nic.in) और [kapil.meena@nic.in](mailto:kapil.meena@nic.in) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकता है।

मसौदा नियम

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप धारा (2) के खंड (त त क) और (त त ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ -** (1) इन नियमों को मसौदा उद्योग (विकास और विनियम) शास्ति, न्यायनिर्णयन और अपील, नियम, 2024 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं -**
  - (1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -
    - (क) 'अधिनियम' से उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;
    - (ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 24क की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत जिला मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
    - (ग) "अपीलकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है;
    - (घ) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
    - (ङ.) "प्रपत्र" से इन नियमों में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।
  - (2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियम में परिभाषित नहीं हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित है।
3. **जांच करना -**
  - (1) अधिनियम की धारा 24क के तहत शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, इसमें विनिर्दिष्ट किसी धारा के किसी प्रावधान के उल्लंघन को दर्शाते हुए किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-I में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अवधि से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
  - (2) उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक नोटिस में, किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।
  - (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।
  - (4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और जिस उल्लंघन के संबंध में आरोप लगाया गया है उसके संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।
  - (5) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को प्रपत्र-II के तहत ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी आगामी तारीख (पहली तारीख से अधिकतम पंद्रह दिनों तक हो और अधिकतम तीन तारीखों तक) तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
  - (6) इन नियमों के अंतर्गत जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी ऐसे व्यक्ति से साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा उसे बुला सकता है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है।
  - (7) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, जांच को आगे बढ़ा सकता है।
  - (8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अनुसार, ऐसी शास्ति लगा

सकता है, जो वह उचित समझे।

- (9) उप-नियम (8) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश में इस अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति लगाने के कारणों को शामिल किया जाएगा।
- (10) उप-नियम (8) के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और उस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
- (11) इस नियम के तहत दिए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (12) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, को नोटिस जारी करने के छः माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- (13) इन नियमों के तहत जारी कोई नोटिस अथवा आदेश निम्न में से किसी एक विधि से उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, नामतः -
  - (i) उक्त व्यक्ति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को देना या भिजवाना; अथवा
  - (ii) व्यक्ति को उसके आवास पर अथवा उसके अंतिम ज्ञात पते पर अथवा उसके अंतिम व्यावसायिक पते अथवा उस कार्यस्थल पर जहां वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है अथवा उस पते पर, जहां उसने लाभ प्राप्ति के लिए अंतिम बार कार्य किया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए; अथवा
  - (iii) यदि खंड (i) अथवा (ii) में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से नोटिस की तामील नहीं की जा सकती तो उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा विशिष्ट हिस्से पर उसे चिपकाया जाएगा जहां वह व्यक्ति रहता है अथवा अंतिम बार रहा है अथवा व्यवसाय किया है अथवा व्यक्तिगत रूप से करता है अथवा लाभ हेतु कार्य किया था।

#### 4. अपील:-

- (1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है तो वह अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (2) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र III में अपील कर सकता है।
- (2) यह अपील, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी: बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, जिस मामले में साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को न स्वीकार करने का पर्याप्त कारण मौजूद है, अपील को स्वीकार कर सकता है और वह लिखित में अवधि के विस्तार के कारणों को दर्ज करेगा।
- (3) अपील के साथ नियम 3 के उप-नियम (8) के तहत जारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न होगी तथा उन तथ्यों का स्पष्ट विवरण प्रदान किया जाएगा, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, अपील का आधार तथा अधिनियम की संगत धारा का उल्लेख होगा।
- (4) अपील, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं अथवा विधिवत रूप से अधिकृत अपने प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की जाएगी।
- (5) डाक से भेजी गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को दायर मानी जाएगी, जिस तारीख को वह प्राप्त हुई है।
- (6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी त्रुटि के बारे में अपीलकर्ता को सूचित करेगा तथा उसे पंद्रह दिनों के भीतर उस त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देगा एवं यदि अपीलकर्ता इस समयावधि के भीतर ऐसी त्रुटि को ठीक करने में विफल रहता है तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा लिखित रूप में कारण दर्ज करके ऐसी अपील को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है तथा अपीलकर्ता को ऐसी अस्वीकृति की सूचना सात दिन की अवधि के भीतर देनी होगी। अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी, उस न्यायनिर्णयन अधिकारी को अपील की एक प्रति भेजेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, साथ ही एक नोटिस भी देगा जिसमें अपीलीय प्राधिकारी को उक्त नोटिस में निर्धारित

अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। नोटिस, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है।

- (7) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी उस व्यक्ति को अपील की एक प्रति भेजेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है, साथ ही एक नोटिस भी देगा जिसमें उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
  - (8) नोटिस, व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से अथवा स्पीड पोस्ट से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
  - (9) अपीलीय प्राधिकारी, संबंधित न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मांगवा सकता है।
  - (10) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझता है।
  - (11) अपीलीय प्राधिकारी अपील स्वीकार करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देगा।
5. समयावधि बढ़ाना - न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्यवाही करने में विलंब या विफल रहने के उचित कारण मौजूद हैं, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अवधि को तब तक बढ़ा सकता है, जिसे वह उचित समझता है।
6. आदेश और शास्ति -
- (1) इन नियमों के तहत प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।
  - (2) इन नियमों के तहत शास्ति के जरिए वसूली गई समस्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

[फा. सं. 9(8)/2020-आईएल]

बालामुरुगन देवराज, संयुक्त सचिव

#### प्रपत्र —I

#### [नियम 3 का उप-नियम (1) देखें]

सेवा में,

.....  
 .....  
 .....

#### कारण बताओ नोटिस

#### विषय: उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

दिनांक ..... (प्रतिलिपि संलग्न) को प्राप्त सूचना के अनुसार .....पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा ..... का उल्लंघन किया गया है

2. उपर्युक्त उल्लंघन के लिए शास्ति लगाई जा सकती है। अतः, आप यह नोटिस प्राप्त होने से .....दिनों के भीतर कारण बताएं कि शास्ति लगाने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24क के तहत आपके विरुद्ध जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णयन अधिकारी

दिनांक और स्थान .....

**प्रपत्र-II**

उल्लंघनकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना

**[नियम 3 का उप नियम (5) देखें]**

सेवा में,

.....

.....

.....

1. मैं/हम, .....

.....

....., दिनांक..... के कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में एतद्वारा, निम्नानुसार बयान प्रस्तुत करते हैं।

.....

.....

2. पिन कोड सहित पूरा पता और राज्य, मोबाइल नंबर और ई-मेल

3. उल्लंघनकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर

**प्रपत्र-III****अपील****[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]**

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी,

.....

.....

1. आवेदक का विवरण:

(i) नाम:

(ii) पत्राचार का पता:

(iii) फोन नंबर:

(iv) ई-मेल:

2. अपील का आधार:

(न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाए)

3. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम....., अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलकर्ता का नाम:

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2024

**G.S.R. 553(E).**—The following draft rules which the Central Government proposes to make under sub-section (2) of section 30 of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft rules may do so in writing within the period so specified to the Secretary, Department For Promotion of Industry And Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Vanijya Bhawan, New Delhi-110001 by post, or electronically at [soil-dipp@nic.in](mailto:soil-dipp@nic.in) and [kapil.meena@nic.in](mailto:kapil.meena@nic.in).

**DRAFT RULES**

In exercise of the powers conferred by clauses (ppa) and (ppb) of sub-section (2) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. —

(1) These rules may be called the draft Industries (Development and Regulation) Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

(b) "adjudicating officer" means the District Magistrate or the Additional District Magistrate authorised under sub-section (1) of section 24A of the Act;

(c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 24B of the Act;

(d) "appellate authority" means an officer authorised under sub-section (1) of section 24B of the Act;

(e) "form" means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Holding of inquiry. —

(1) For the purpose of adjudication of penalties under section 24A of the Act, on receipt of any complaint indicating any contravention of any provision of any section specified therein, the adjudicating officer shall,

issue a notice in Form-I to such person, requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-II as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the person against whom the inquiry was held.

(12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.

(13) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:-

(i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) If it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

#### 4. Appeal. —

(1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under sub-section (2) of section 24B of the Act in Form-III.

(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of sixty days from the date of the order. Provided that, the appellate authority may, where sufficient cause for not preferring the appeal within such period of sixty days is given, he may admit the appeal and record the reasons for such extension in writing.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellant authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellant authority may by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant with a period of seven days thereof. On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the adjudicating officer against whom the appeal is sought along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice. The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(7) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the person against whom the appeal is sought along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.

(8) The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

5. Extension of time. — The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

6. Order and penalties. —

(1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

[F. No. 9(8)/2020-IL]

BALAMURUGAN DEVRAJ, Jt. Secy.

### Form —I

[See sub-rule (1) of rule 3]

To

.....  
.....  
.....

### SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Contravention of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

Sir/Madam,

As per intimation ..... dated (copy enclosed), a contravention has been committed under ..... section of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 at .....



2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ..... days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 24A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act.

Adjudicating officer

Date and place .....

## FORM-II

### Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

[See sub-rule (5) of rule 3]

To

.....  
 .....  
 .....

1. I / we .....

.....  
 .....hereby give a  
 statement in reference to the show cause notice dated  
 .....  
 .....

2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail:

3. Signature of the contravener or his authorized representative:

4. Name of the person along with mobile number who has signed:

## FORM-III

### Appeal

[See sub-rule (1) of rule 4]

To

Appellate Authority,

.....  
 .....

1. Particulars of appellant:

- (i) Name:
- (ii) Address for correspondence:
- (iii) Contact Number:
- (iv) Email:

2. Grounds of appeal:

(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

I/We....., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant: